

Ref No: PSB/HO/Shares Cell / 29 /2025-26

July 15, 2025

To,

| | |
|--|--|
| BSE Limited, Department of Corporate Services, 25 th floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001. SCRIP ID : PSB SCRIP CODE : 533295 | National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, C – 1, Block – G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051. SYMBOL: PSB SERIES: EQ |
|--|--|

Dear Sir,

Reg: 15th Annual General Meeting: Newspaper Publication

In continuation to our letter dated July 14, 2025, the notice of the 15th Annual General Meeting was also published in the newspapers on July 15, 2025.

The copy of the notice published in Business Standard (English and Hindi newspaper) on July 15, 2025 is attached herewith for reference.

You are requested to take a note of the same.

Yours faithfully

Saket Mehrotra
Company Secretary



Head Office: 21, Rajendra Place, New Delhi-110008

Corporate Office: NBCC Office Complex, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi – 110023

Email: complianceofficer@psb.co.in

सीमा प्रबंधन पर ध्यान दें भारत-चीन

विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक के दौरान व्यापारिक बाधाओं से बचने पर दिया बल

अर्विस मोहन

लगभग छह वर्षों में अपनी पहली चीन यात्रा पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी से कहा कि भारत-चीन सीमा पर टकराव का समाधान निकालने से तनाव कम हुआ है। अब दोनों देशों की अपने संबंधों को सकारात्मक रूख देने के लिए सीमा प्रबंधन और विवाद निपटाने सहित अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों पड़ोसियों को अपने नागरिकों के बीच संपर्क को सामान्य बनाना चाहिए और प्रतिबंधात्मक व्यापार उपायों और बाधाओं से बचना चाहिए। उन्होंने एक-दूसरे की सीमा से बहने वाली नदियों पर सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया और चीनी पक्ष से जल विज्ञान संबंधी डेटा दोबारा प्रदान करने का आग्रह किया।

पेइचिंग में वांग के साथ बैठक में अपने शुरुआती भाषण में जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध इस आधार पर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकते हैं कि मतभेद विवाद का रूप न लें और आपसी प्रतिस्पर्धा संघर्ष में तब्दील न हो।

चीन द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति को प्रतिबंधित करने और लोगों के बीच पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए जयशंकर ने



विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की

कहा, ‘इस संदर्भ में यह भी आवश्यक है कि प्रतिबंधात्मक व्यापार उपायों और बाधाओं से बचा जाए।’ जयशंकर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह वांग के साथ इन मुद्दों पर और विस्तार से चर्चा करेंगे।

जयशंकर रविवार को सिंगापुर की एक दिवसीय यात्रा के बाद थ्यानचिन में होने वाली शॉघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए पेइचिंग पहुंचे हैं। चीन एससीओ का वर्तमान अध्यक्ष है और वह इस साल के अंत में थ्यानचिन में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाग लेने की संभावना है। जयशंकर ने आखिरी बार 11

से 13 अगस्त, 2019 तक चीन का दौरा किया था। उस वर्ष जून में भारत के विदेश मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनकी पहली यात्रा थी।

जैसा कि जयशंकर ने अपनी टिप्पणियों में उल्लेख किया, मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में मुलाकात के बाद भारत-चीन संबंध धीरे-धीरे सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जयशंकर ने कहा, ‘हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस गति को बनाए रखें।’ उन्होंने कहा कि भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों के लिए आवश्यक है कि हम अपने संबंधों के लिए दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाएं। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि वांग और

छह वर्षों बाद चीन दौरा

■ अपने संबंधों को सकारात्मक रूख देने के लिए सीमा प्रबंधन और विवाद निपटाने सहित अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें दोनों देश

■ एक-दूसरे की सीमा से बहने वाली नदियों पर सहयोग जल विज्ञान संबंधी डेटा दोबारा देने का आग्रह किया

■ संबंध इस आधार पर आगे बढ़ें कि मतभेद विवाद का रूप न लें और प्रतिस्पर्धा संघर्ष में तब्दील न हो

वह हाल के महीनों में कई अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में मिल चुके हैं। दोनों ने रणनीतिक संवाद किया है। जयशंकर ने कहा, ‘हमारी अपेक्षा है कि यह अब नियमित होगा और एक-दूसरे के देशों में होगा।’ मालूम हो कि 2020 के जून-जुलाई में गलवान संघर्ष के बाद भारत-चीन विदेश मंत्रियों के स्तर की वार्ता बंद कर दी गई थी।

जयशंकर ने दोनों पड़ोसियों के बीच स्थिर और रचनात्मक संबंधों का आह्वान किया, जो आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी संवेदनशीलता के आधार पर बेहतर तरीके से किया जा सकता है। उन्होंने कहा, ‘हमने पहले भी सहमति व्यक्त की है कि मतभेद विवाद नहीं बनने चाहिए और न ही

हवाई अड्डों के पास बढ़ रहीं जमीन की कीमतें

संकेत कोल

देश के प्रमुख हवाई अड्डों के आसपास रिहायशी अपार्टमेंट और प्लॉट की कीमतें आसमान छू रही हैं। इनमें पांच वर्षों के दौरान लगभग दोगुने की वृद्धि हो चुकी है। रियल्टी रिसर्च फर्म स्क्वैर याड्स की सोमवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली से सटे यमुना एक्सप्रेसवे, पनवेल क्षेत्र, उत्तरी बेंगलुरु और दक्षिणी हैदराबाद जैसे प्रमुख हवाई अड्डों के पास के छोटे बाजारों में संपत्ति की कीमतें वित्त वर्ष 21 से वित्त वर्ष 25 के बीच 69 से 90 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं। इसी अवधि के दौरान इन शहरों में अपार्टमेंट की औसत कीमतों में 45 से 79 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।

इन क्षेत्रों में आवासीय प्लॉटों के मूल्यों में चार साल की अवधि में 84 से 118 प्रतिशत की उछाल आई है। तुलनात्मक रूप से पूरे शहर की बात करे तो आवासीय प्लॉटों की कीमतें 45 से 93 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं। स्क्वैर याड्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और संस्थापक तनुज शौरी ने कहा, ‘देश में प्रमुख हवाई अड्डों वाले दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों ने अपने यहां बेहतर सड़कें, रोजगार केंद्रों में



वृद्धि और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे में निवेश किया है। यही वजह है कि यहां रहने के लिए लोग आक र्षित हो रहे हैं।’

फर्म ने कहा कि हवाई अड्डा परियोजना की घोषणाओं के बाद सट्टेबाजी और डेवलपर्स की बढ़ती रुचि के कारण आवासीय, ऑफिस और हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट की परियोजनाओं के साथ-साथ हवाई अड्डे से जुड़े विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) की मांग में तेजी आई है। हवाई अड्डे वाले शहरों में संपत्ति की कीमतों में उछाल से संबंधित यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब पिछले महीने ही अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान 171 सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद कुछ दूरी पर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस दुर्घटना के बाद से हवाई अड्डों के आसपास रहने के प्रति लोगों में डर का माहौल है।

लोक सभा में हाजिरी की नई व्यवस्था होगी

लोक सभा आगामी मॉनसून सत्र से अपने सदस्यों के लिए उपस्थिति दर्ज कराने की नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है, जिसके तहत वे लॉबी में जाकर नहीं, बल्कि अपनी आवंटित सीट पर ही उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। इससे समय की बचत होगी, क्योंकि लॉबी में कई बार एकसाथ कई सांसदों के पहुंचने के कारण उपस्थिति दर्ज कराने में समय लग जाता है। सूत्रों ने बताया कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ सांसद सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिए बिना ही अपनी उपस्थिति दर्ज करारक चले जाते हैं।

लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला इस नई व्यवस्था को लागू करने के इच्छुक हैं और लॉबी में उपस्थिति रजिस्टर की व्यवस्था कुछ समय जारी रहेगी, ताकि सांसदों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से परिचित होने का समय मिल जाए। बिरला ने पिछले साल संसद को कागज रहित बनाने के प्रयासों के तहत सहस्रमंजरी को लॉबी में एक इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट पर डिजिटल पेन का उपयोग करके सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का विकल्प दिया था। मंत्रियों और नेता प्रतिपक्ष को उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है।

भाषा

शुभांशु की वापसी का सफर शुरू

डैगन ग्रेस अंतरिक्ष यान के सोमवार को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) से अलग होने के

साथ शुभांशु शुक्ला और वाणिज्यिक ऐक्सिअम-4 मिशन के तीन अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की पृथ्वी की वापसी यात्रा शुरू हो गई। पिछले 18 दिनों से चारों अंतरिक्ष यात्री आईएसएस पर थे। डैगन अंतरिक्ष यान आईएसएस से भारतीय समयानुसार शाम 4:45 बजे अलग हुआ। इसमें मूल कार्यक्रम से 10 मिनट की देरी हुई तथा कक्षीय प्रयोगशाला से दूर जाने के लिए उसने दो बार थ्रस्टर्स चालू किए। शुक्ला, कर्मांडर पैमी क्विटसन, तथा मिशन विशेषज्ञ पोलैंड के स्लावोच्च उज्जान्स्की-विस्नीव्स्की और हंपरी के टिबोर काफ़ू सहित ऐक्सिअम-4 के चालक दल ने 26 जून को आईएसएस से जुड़ने के बाद से लगभग 76 लाख मील की दूरी तय करते हुए पृथ्वी के चारों ओर लगभग 433 घंटे या 18 दिन में 288 परिक्रमाएं कीं। गले मिलने और हाथ मिलाने के बाद, चारों अंतरिक्ष यात्री अनडॉकिंग से लगभग दो घंटे पहले डैगन अंतरिक्ष यान में प्रवेश कर गए, अपने स्पेससूट पहन लिए और भारतीय समयानुसार अपराह्न 2:37 बजे अंतरिक्ष यान को आईएसएस से जोड़ने वाले हैच को बंद कर दिया। रविवार को आईएसएस पर विदाई समारोह में शुक्ला ने कहा, ‘जल्दी



डैगन के आईएसएस से अलग होते ही धरती की ओर चले शुभांशु शुक्ला

ही धरती पर मुलाकात करते हैं।’ राकेश शर्मा के 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा करने के बाद शुक्ला दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। अंतरिक्ष स्टेशन के आसपास के सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद, अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी पर वापसी की 22.5 घंटे की आरामदायक यात्रा के लिए अपने स्पेससूट उतार दिए। डैगन ग्रेस अंतरिक्ष यान द्वारा मंगलवार को भारतीय समयानुसार दोपहर 3:01 बजे कैलिफ़ोर्निया टेट पर पहुंचने के लिए डी-ऑर्बिट प्रक्रिया शुरू करने से पहले, अंतरिक्ष यात्री एक बार फिर स्पेससूट पहनेंगे। चारों अंतरिक्ष यात्रियों को ऑडीएसएस में सात दिन बिताने होंगे, क्योंकि उन्हें कक्षा में अनुभव की जाने वाली भारहीनता के विपरीत, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव

में पृथ्वी पर जीवन के लिए खुद को ढालना होगा।

पूरा देश कर रहा इंतजार

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूरा देश शुभांशु के वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सिंह ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘शुभांशु, आपका स्वागत है! पूरा देश आपके घर वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। एक्सिओम 4 के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सफलतापूर्वक अलग होने के साथ आपकी वापसी यात्रा शुरू हो रही है।’

परिवार में उत्साह का माहौल
लखनऊ में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का परिवार उनकी सुरक्षित वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है और परिवार ने इसे बेहद गर्व और भावनात्मक उत्साह का क्षण बताया है। परिवार ने कहा कि उनके लिए यह बेहद खुशी की बात है। शुभांशु ने उन्हें ‘एक बच्चे की तरह’ अंतरिक्ष के नजारे दिखाए। शुभांशु के पिता शंभू दयाल शुक्ला ने अपने बेटे के अंतरिक्ष मिशन में सहयोग के लिए जनता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, ‘हम अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए जनता और माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं।

तीन राज्यों में नए राज्यपाल

केंद्र सरकार ने तीन राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। पूर्व नगर विमानन मंत्री पी. अशोक गजपति राजू को सोमवार को गोवा का नया राज्यपाल बनाया गया, जबकि जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री कवींद्र गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है।

विज्ञप्ति के अनुसार, पश्चिम बंगाल से भाजपा के वरिष्ठ नेता अशीम कुमार घोष हरियाणा के नए राज्यपाल होंगे। इसमें कहा गया कि

उनकी नियुक्तियां उनके कार्यभार संभालने की तिथि से प्रभावी होंगी। आंध्र प्रदेश से तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के नेता राजू गोवा के राज्यपाल के रूप में पी.एस. श्रीधरन पिल्लई का स्थान लेंगे। पिल्लई ने 15 जुलाई, 2021 को गोवा के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। राजू (74) ने 27 मई, 2014 से 10 मार्च, 2018 तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में नगर विमानन मंत्री के रूप में काम किया। वह आंध्र प्रदेश सरकार में भी मंत्री पद संभाल चुके हैं।

भाषा

Kothari Hosiery Factory Private Limited
29, Strand Road, Mohta House 2nd Floor, Kolkata 700001
P 84208 26999, www.kotharihosiery.com

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत का एक बैंक)

प्रधान कार्यालय - 21, राजेन्द्र पैसेज, नई दिल्ली-110008
कॉर्पोरेट कार्यालय - एनवीपीसी कार्यालय कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक 3, पूर्वी किंगडॉम नगर, नई दिल्ली-110023
वेबसाइट - <https://punjabandsindbank.co.in/>

काबटें सोसाटी की जीवन-कालीय

विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य श्रव्य-दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाने वाली बैंक की 15वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम की सूचना में उल्लिखित व्यावसायिक मर्कों को संपादित करने के लिए भारतीय प्रतिसूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी विभिन्न परिचर्यों के अनुसरण में **मंगलवार, 05 अगस्त, 2025** को प्रातः 11.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य श्रव्य-दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की 15वीं वार्षिक साधारण बैठक का आयोजन किया जाएगा।

टिप्पणियाँ:

- पूर्वोक्त परिचर्यों के अनुपालन में बैंक की 15वीं वार्षिक साधारण बैठक सूचना समाविष्ट वार्षिक रिपोर्ट 2024–25 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ उन समस्त शेयरधारकों को भेजी गई हैं जिनके ई-मेल पते, बैंक/निक्षेपागार सहभागियों के पास पंजीकृत हैं तथा उन शेयरधारकों को भी भेजी गई है जिन्होंने 08 जुलाई, 2025 को प्रकाशित हमारे समाचार पत्र प्रकाशन के अनुसारण में हमारे आरटीए, एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास आई ई-मेल पते पंजीकृत किए हैं। इसकी प्रति बैंक वेबसाइट अर्थात <https://punjabandsindbank.co.in/> और शेयर बाजारों की वेबसाइट www.nseindia.com व www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। वार्षिक साधारण बैठक के लिए मानित स्थान, बैंक का प्रधान कार्यालय होगा।
- अंतिम तिथि/निर्दिष्ट तारीख को मौंतिक रूप या डीमेट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) की इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली ("दूरस्थ ई-मतदान") के माध्यम से 15वीं एजीएम की सूचना में उपवर्णित रूप में व्यावसायिक कार्यकलापों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं।
- शेयरधारकों को आगे सूचित किया जाता है कि:
 - 15वीं एजीएम सूचना में उपवर्णित रूप में व्यावसायिक कार्यकलापों का संपादन, 15वीं एजीएम में दूरस्थ ई-मतदान या ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।
 - बैंक की 15वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना समाविष्ट वार्षिक रिपोर्ट 2024–25 का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण **सोमवार, 14 जुलाई, 2025** को पूर्ण हो गया है।
 - बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर अंतरण रजिस्टर, लामांश और 15वीं वार्षिक साधारण बैठक के उद्देश्य से **बुधवार, 30 जुलाई 2025 से मंगलवार, 05 अगस्त 2025 तक** (दोनों दिवस सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।
 - लामांश, ई-मतदान और वीसी/ओएवीएम के माध्यम में सहभागिता हेतु शेयरधारकों के अधिकारी की संगणना के लिए अभिलिखित तिथि **मंगलवार, 29 जुलाई 2025** है। वार्षिक साधारण बैठक में लामांश घोषणा की तिथि से 30 दिनों के भीतर शेयरधारकों को लामांश का भुगतान किया जाएगा। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि आयकर अधिनियम 1961 (अधिनियम) की धारा 194 के अनुसार, यदि किसी शेयरधारक को ₹50000/- (रुपये पाँच हजार मात्र) से अधिक के लामांश भुगतान किया जाता है तो बैंक, उस पर कर की कटौती करेगा। इस संबंध में **08 जुलाई, 2025** को प्रकाशित हमारे समाचार पत्र प्रकाशन के माध्यम से भी शेयरधारकों को सूचित किया गया था कि **29 जुलाई, 2025 को अपराह्न 05:00 बजे तक** या उससे पूर्व हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट, एमयूएफजी इनटाइम प्राइवेट लिमिटेड के पास आवश्यक दस्तावेज/ फॉर्म प्रस्तुत करें।
 - दूरस्थ ई-मतदान शुक्रवार, **01 अगस्त 2025** को प्रातः **10:00 बजे** आरंभ होगी तथा **सोमवार, 04 अगस्त, 2025 को अपराह्न 05:00 बजे** समाप्त हो जाएगी, उसके पश्चात इसे अक्षम कर दिया जाएगा।
 - कोई भी व्यक्ति जो बैंक शेयर्स का अभिग्रहण करता है तथा 15वीं एजीएम की सूचना-प्रेषण के बाद सदस्य बनता है तथा अंतिम तिथि/विनिर्दिष्ट तिथि अर्थात **मंगलवार, 29 जुलाई 2025** को शेयर धारित करता है, एजीएम के दौरान दूरस्थ ई-मतदान तथा ई-मतदान हेतु लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए एजीएम सूचना में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करें।
 - शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि:
 - 15वीं एजीएम के दौरान भी मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी तथा वीसी सुविधा के माध्यम से 15वीं एजीएम में उपस्थित शेयरधारक जिन्होंने दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से सक्रिय पर अपना मतदान नहीं किया है तथा अन्यथा जिन्हें ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, 15वीं एजीएम में ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान हेतु पात्र होंगे;
 - शेयरधारक सदस्य जिन्होंने 15वीं एजीएम से पूर्व दूरस्थ ई-मतदान प्रणाली द्वारा अपना मतदान किया है, वे भी 15वीं एजीएम में सहभागिता कर सकते हैं लेकिन पुनः मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे; तथा
 - अंतिम तिथि/विनिर्दिष्ट तारीख को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लामांशी रचामी के रजिस्टर में अभिलिखित नाम वाले व्यक्ति ही दूरस्थ ई-मतदान या 15वीं एजीएम में ई-मतदान की सुविधा के लिए पात्र होंगे।
 - अमूर्त रूप, मूर्त रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक तथा वे शेयरधारक जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, के लिए दूरस्थ रूप से मतदान करने की शिष्टता, 15वीं एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराया गया है।
 - यदि आपको एजीएम में सहभागिता करने और सीडीएसएल ई-मतदान प्रणाली से ई-मतदान के संबंध में किसी प्रकार की जिज्ञासा या प्रश्न हैं तो helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल कर सकते हैं अथवा टोल-फ्री नंबर 1800-22-5533 पर संपर्क कर सकते हैं।
 - इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान की सुविधा से संबंधित समस्त शिकायतों के लिए श्री राकेश दत्तवी, वरिष्ठ प्रबंधक (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं तल, मेरथन प्लसुर, मफतलाल मिल कॉम्प्लेज, एन एम जोगी मार्ग, लोअर पेरल (पूर्व), मुंबई-400013 से संपर्क किया जा सकता है अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करें अथवा टोल-फ्री नंबर 1800-22-5533 पर कॉल करें।
 - शेयरधारकों से अनुरोध है कि किसी अन्य जानकारी/प्रक्रिया के लिए पूर्वोक्त उपलब्ध अनुसार विकसित एजीएम सूचना का संदर्भ लें।
- दूरस्थ ई-मतदान तथा एजीएम में ई-मतदान का संकलित परिणाम, एजीएम के 02 (दो) कार्य-दिवस के भीतर बैंक की वेबसाइट <https://punjabandsindbank.co.in/> शेयर बाजारों की वेबसाइट www.nseindia.com और www.bseindia.com तथा सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।
- 15वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना समाविष्ट वार्षिक रिपोर्ट 2024–25, <https://punjabandsindbank.co.in/content/archive-annual> पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक (साकेत मेहरोत्रा) कंपनी सचिव

भारत में फरटि भरेगी टेस्ला, बीकेसी में खुला पहला शोरूम

अंजलि सिंह और प्राची पिसाल

इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली दिग्गज अमेरिकी कंपनी टेस्ला मंगलवार को भारत में कदम रख रही है। कंपनी वाई एसयूवी मॉडल के साथ देश में दस्तक दे रही है। कंपनी ने मुंबई के पॉश इलाका माने जाने वाले बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में अपना स्टोर खोला है, जो इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में तेजी से आगे बढ़ रहे भारत में टेस्ला के प्रवेश का प्रतीक है।

आप जब यह खबर पढ़ रहे होंगे तो उसके कुछ घंटों में टेस्ला का पहला शोरूम खुलने वाला होगा। बीकेसी के पॉश वाणिज्यिक रियल एस्टेट मेकर मैक्सिटी में 4,000 वर्ग फुट में फैले इस शोरूम में तैयारियों जोर-शोर से चल रही हैं। मगर इसमें काफी गोपनीयता भी बरती जा रही है। मेकर मैक्सिटी के किरायेदारों में प्रमुख इन्वेस्टमेंट बैंक सॉवरिन वेल्थ फंड आदि का नाम शामिल है। इसके अलावा ऐपल स्टोर और जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल भी कुछ ही दूरी पर है।

टेस्ला के स्टोर का प्रवेश द्वार सफेद पर्दों और काले कपड़ों से ढका है, जिससे एस्टेट के लोगो और अंदर रखी वाई मॉडल की थोड़ी सी झलक मिल पा रही है। कांच के भीतर देखने पर एक सफेद और काली कार दिख रही है, जिसे देखने पर लग रहा है कि यह वाई मॉडल की कार है।

मंगलवार की सुबह 10 बजे भारत में आधिकारिक तौर पर टेस्ला का अनावरण किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर लोग काफी कयास लगा रहे हैं मगर मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि इस में टेस्ला के सह-संस्थापक और मुख्य कार्य अधिकारी ईलॉन मस्क शामिल नहीं होंगे। हालांकि, मस्क के आने के बारे में पूछे जाने के लिए टेस्ला को भेजे गए ईमेल का खबर प्रकाशित होने तक कोई जवाब नहीं मिला।

आयोजन को लेकर लोगों के बीच ज्यादा उत्साह



कंपनी वाई एसयूवी मॉडल के साथ देश में दस्तक दे रही है। शोरूम के आसपास सुरक्षा के किए गए हैं कड़े इंतजाम

भारत में ईवी को उड़ान

■ टेस्ला के स्टोर का प्रवेश द्वार सफेद पर्दों और काले कपड़ों से ढका है, जिससे टेस्ला के लोगो और अंदर रखी वाई मॉडल की थोड़ी सी झलक मिल पा रही है

■ बीकेसी के पॉश वाणिज्यिक रियल एस्टेट मेकर मैक्सिटी में 4,000 वर्ग फुट में फैले इस शोरूम के आसपास सुरक्षा व्यवस्था सख्त, तस्वीरें लेने पर भी मनाही

■ शोरूम के उद्घाटन में शामिल नहीं होंगे कंपनी के सह-संस्थापक ईलॉन मस्क

देखने को नहीं मिल रही है। शोरूम के आसपास दर्शकों की खास भीड़ भी नहीं है। आम लोगों के प्रवेश पर भी सख्ती की गई है और आने वाले लोगों को केवल निर्धारित बैठकों में ही शामिल होने के लिए कहा गया है। सुरक्षाकर्मियों की तैनाती बाहर से नहीं की गई है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक-चौबंद रखी गई है कि शोरूम के आसपास तस्वीरें लेने पर भी रोक लगा दी गई है।

शोरूम के आसपास की नीति की जानकारी रखने

वाले एक शख्स ने कहा, ‘मेकर मैक्सिटी के पास सुरक्षा व्यवस्था हमेशा कड़ी रहती है। किसी भी चीज को आसानी से अंदर लाया ले या बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। यह सामान्य प्रोटोकॉल का ही हिस्सा है।’

टेस्ला अपने शोरूम की तैयारियों पर पूरी नजर रख रही है। कंपनी ने सुरक्षा अथवा सफाई की जिम्मेदारी के लिए बाहर के किसी ठेकेदार को काम नहीं सौंपा है। शोरूम की काफी अच्छे तरीके से साफ-सफाई की जा रही है, जिसमें मार्बल के फर्श की पॉलिशिंग



Upwardly mobile

An agile government-private partnership has proved a win-win for the mobile PLI scheme. Can the model be replicated for others?

SURAJEET DAS GUPTA
New Delhi, 14 July

Just two months after Prime Minister Narendra Modi returned to power with a thumping majority in May 2019 for a second time, Nripendra Misra, then the principal secretary to the PM, set up a committee to evaluate India's potential to "become a manufacturing hub" for mobile devices.

The timing was opportune. American President Donald Trump, then in his first term, had already unleashed a US-China tariff war. Multinationals from China — the world's largest manufacturing hub — were looking for alternative manufacturing destinations to find their way around the China Plus One strategy. Meanwhile, companies like Apple Inc had started talking to the Indian government to set up shop here.

Amnabhat Kant, then NITI Aayog's CEO, was tasked to head the committee, which would include secretaries from the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) under the commerce ministry and the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY). They were asked to build a framework to identify India's "cost disability" (with competing countries such as China and Vietnam, for instance, India had a disability of 16-18 per cent). They were also asked to assess the opportunities arising out of trade disputes, and suggest possible fiscal and non-fiscal interventions.

What followed were marathon rounds of conversations with stakeholders — like Apple Inc and Samsung, which showed serious interest — and the government. Those in the know say it took over 35 meetings and 13 months for things to fructify — nine months to close the mobile devices production-linked incentive (PLI) scheme in April 2020 and another four to finalise the guidelines.

Five years on, it is safe to say that the PLI scheme for mobile phones has been a resounding success. For the world, it is proof of India's ability to become a global manufacturing hub.

With the scheme scheduled to end in 2025-26 (FY26) — it was extended for a year because of the Covid-19 pandemic — companies are pushing for it to be extended for a few more years to tide over the tariff challenges posed by the US.

The numbers are telling. During the PLI years, the overall mobile production has doubled, from under \$30 billion to \$64 billion, with 99 per cent of domestic demand met by "made in India" phones. Exports have increased eight times, from nearly \$3 billion before the scheme began to \$24 billion, making smartphones India's single-largest export (based on the Harmonised System codes used

to classify traded products globally). And the scheme has helped electronics become India's third-largest export, behind engineering goods and petroleum.

Today, one out of every five phones that Apple Inc sells globally comes from India. The Cupertino (California)-based company, which has been a major beneficiary of the PLI scheme, had made a cautious entry into India, committing to shift 10 per cent of its production value of iPhones from China to India.

However, in the first four years, it has nearly doubled that target.

Direct investments by companies tapping into PLI have exceeded expectations, crossing ₹11,800 crore. Until June 2025, these companies together generated over 136,000 direct jobs. Apple Inc and its ecosystem of suppliers has alone created nearly 200,000 direct jobs, with the mobile major expanding its supply chain in India.

While the PLI scheme for many other sectors faced delays in handing out incentives, MeitY worked out an efficient system of disbursements for mobile PLI.

So far, smartphone PLI participants have received upwards of ₹12,500 crore of the total ₹21,500 crore disbursed to 14 sectors under the PLI scheme. That's nearly 58 per cent of the total amount disbursed.

Companies under the mobile scheme have, however, claimed 35 per cent so far of the total ₹34,000 crore allocated to the mobile devices PLI across five years. The claims are low because the PLI scheme aims to build

homogenous "Indian champions". Also, the performance of some global players has faltered — they have failed to meet the conditions required on incremental investment and production value.

That said, PLI's beneficiary companies, which mainly include Apple Inc vendors, Samsung, and Dixon, among others — say this figure is expected to cross ₹25,000 crore, close to 70 per cent of the amount originally allocated. The scheme has been a bonanza for the government, too. The mobile devices industry has financed the PLI scheme many times over. For instance, the finance ministry increased the goods and services tax (GST) on smartphones from 12 per cent to 18 per cent the very week the PLI scheme was launched, in April 2020. This 6 per cent GST increase will deliver nearly ₹1 trillion by the end of this fiscal year — four times the amount allocated for smartphones PLI. In fact, in the five years of the scheme, the cumulative tax collected — which includes GST, Customs duty and corporate tax — from mobile devices would be around ₹3 trillion. That's 150

per cent more than the total Budget incentive allocation for all PLIs put together.

Two to tango
So why has mobile PLI succeeded despite attacks from

critics and some economists, while many others have not? The answer lies in the private-government collaboration — with multiple ministries, such as MeitY, DIPPE, commerce, and finance

Government of Kerala
Published Tenders from 10-07-2025 to 13-07-2025
Kerala Fire and Rescue Services
Tender ID: 2025 FRS 775639 1st Director General *
PURCHASE OF 6 NOS OF METAL CUTTER (BATTERY OPERATED) * Closing Date: 14-Aug-2025 * PAC: ₹750000
Visit <https://etenders.kerala.gov.in> for more details.
Ro.No:10-13/Jul/2025/PRD/NIS

AARVI ENCON LIMITED
CIN: L29290MH1987PLC045499
Regd. Office: 603, 51 Wing, Marathon Innova, Marathwada, Mumbai - 400 013. Phone Nos.: +91-22-4049 9999
Email ID: info@aarviencon.com; www.aarviencon.com

NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY
In continuation to our newspaper advertisement dated July 12, 2025, NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of the members of Aarvi Encon Limited (the "Company") will be held through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") on **Friday, August 8, 2025 at 11.00 A.M. IST**, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with Circulars dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, January 13, 2021, December 14, 2021 and May 05, 2022 and September 19, 2024 as issued from time to time and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and (collectively referred to as "relevant circulars") and the SEBI Circulars ("SEBI Circulars") as amended and issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") the latest Circular being Circular No. SEBI/HO/CFD-PD-2/P/2024/133 dated October 03, 2024, to transact the business as set forth in the Notice calling the AGM.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the 37th AGM of the Company and the Standalone and Consolidated financial statements for the financial year 2024-25, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents as mentioned in the attached thereto, have been dispatched on **July 14, 2025** only through electronic mode to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s) / Registrar & Share Transfer Agents viz. The Notice along with the aforesaid documents are also available on the Company's website at: www.aarviencon.com and the website of National Securities Depository Limited (NSDL) i.e. <https://www.evoting.nsdl.com> and on the website of the Stock Exchange of India, i.e. National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and relevant provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is pleased to provide its members with the remote e-voting facility to cast their vote electronically on the resolutions mentioned in AGM through the electronic voting platform provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The facility of electronic voting shall also be made available during the meeting on the day of the AGM for those members who have not casted their vote by remote e-voting. The Board has appointed M/s. Amity Nadiyal & Associates, Practising Company Secretaries, as Scrutinizer for conducting the voting process in a fair and transparent manner. The members may note the following:

- Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on Cut-off date i.e. **Friday, August 1, 2025** may cast their vote electronically or as on the Record Date i.e. **Friday, August 1, 2025** shall be eligible for the Dividend subject to the approval of the shareholders in AGM.
- he remote e-voting period commences from **Tuesday, August 5, 2025 at 10:00 A.M. (IST)** and ends on **Thursday, August 7, 2025 at 05:00 P.M. (IST)**. The remote e-voting facility shall be disabled thereafter by NSDL. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
- any person, who acquires shares and becomes a member of the Company after sending the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. August 1, 2025 may obtain the login ID and password by sending an email to cs@aarviencon.com by mentioning his/her folio number/DP ID and client ID number. However, if you are already registered with NSDL for e-voting, then you can use your existing User ID and password for casting your vote.
- The facility of voting through electronic voting system shall also be made available at the AGM and the members participating in AGM through VC/OAVM, who have not cast their vote by remote e-voting shall be available to exercise their right in the meeting.
- The members who have already cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM through VC/OAVM, but shall not be entitled to cast their vote again in the meeting.
- Any person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owner maintained by the depository as on the cut-off date, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the meeting.
- The Company requests all the shareholders who have not yet registered their email addresses or have not updated their email addresses with the Depository to register the same within 3 days of service of this public advertisement.

The process of registration of email address is provided below:

- The shareholders who have not registered their email addresses can get the same registered by furnishing the details to their depository participant, in case the shares are held in demat form.
- The Company has appointed the services of National Depository Services Limited to extend the e-voting facility to all the shareholders to cast their votes in electronic way on all resolutions set forth in the Notice of the AGM. The instructions for casting the votes through remote e-voting for shareholders holding shares in demat and who have not registered their email IDs, shall form part of the Notice of the AGM and the details shall also be hosted at the website of the Company at www.aarviencon.com and also shall be available on the website of <https://www.evoting.nsdl.com>.
- Members are requested to update their Electronic Bank Mandate with their respective DPs for receiving the dividends directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service.
- Members, who need assistance before or during the AGM, may send request at evoting@nsdl.co.in or call at 022-4886 7000 and 022-24987000 or may send an email Ms. Veena Savarna on veenas@nsdl.co.in.
- For any query/clarification or assistance required with respect to Annual Report 2024-25 or Annual General Meeting, the Members may write to cs@aarviencon.com.

Date : July 15, 2025
Place : Mumbai
By Order of the Board
For Aarvi Encon Limited
Sd/-
Leela S. Bhatt
Company Secretary

Gainers & gainers

For companies

- Mobile phone production doubled from \$30 bn to \$64 bn during the PLI period
- Exports up eightfold from \$3 bn before PLI to \$24 bn in FY25
- Cumulative direct investment of ₹11,800 cr made through PLI players
- One out of every 5 iPhones sold globally made in India
- Direct employment to 136,000 till the end of June 2025

working in tandem.

MeitY also tweaked its policy to accommodate the companies' requirements. For one, the value addition norms at the start of PLI, though not mandatory, were expected to hit 35-40 per cent in the final year, but currently stand at just over 20 per cent.

"We told the government that initially the focus should be on scale, and value addition could follow. Even China took many decades to reach 40 per cent. They appreciated the issue," says a top executive of a PLI beneficiary company who does not wish to be named.

MeitY responded by announcing a fresh PLI scheme for electronics components with a budget of ₹22,919 crore. With the expectation that over 150 companies would be accommodated, the government expects India to have a vibrant global supply chain, which would enhance localisation faster.

The government also

endorsed the view that with China-India joint ventures off the table after the Galwan clash, finding local, non-Chinese supply chain partners would be a slow process and could take 3-5 years.

Apple Inc, after pursuing Chinese talent to come in, changed tack. It has turned to Indian companies — such as Tata, Vishay, and Wipro, along with dozens of micro, small and medium enterprises (MSMEs) — to join its global supply chain.

At the end of FY24, Apple had 20 domestic vendors; it plans to take that number up to nearly 50 this year. It has also roped in companies like Japan's TDK to set up operations in India for phone batteries. Apple Inc revenues from domestic sales, incidentally, hit ₹67,000 crore in FY24.

The government also shifted its stance as and when needed. For instance, it had earlier insisted that only the depreciated value of imported secondhand machines would apply for calculating

incremental investment under PLI. Many of the machines coming from China are secondhand. It related following opposition from global mobile players, who said this was unfair since they were primarily shifting part of their production from one country to another.

Also, the Free On Board, or FOB, value of a phone that could be exported was initially pegged at \$300 and above. This was brought down to \$200 since it would otherwise benefit only Apple Inc. Samsung had many phones that cost less. Similarly, the incremental investment requirement of ₹3,000 crore was brought down by a third as some companies had already set up new factories before the scheme was announced.

Mobile PLI is an example of how extensive consultations and partnership with the government and the private sector can change the game. Says a senior executive

For government

- Incremental GST imposed during PLI years on phones will generate ₹1 trillion — four times what has been disbursed as incentives
- Taxes paid by mobile device players during PLI years will be 150% more than collective allocation to all 14 PLI schemes

who has worked closely on PLIs: "There are clear lessons — avoid spreading incentives too thin like the previous MEIS (Merchandise Exports from India Scheme) had done; define policy objectives clearly (is it for exports, or import substitution, or strategic objectives?); be flexible; don't hardwire value addition or timeline details; and have an 'all of government' approach. Then you have a winner."

Apple and Samsung's export successes have also drawn other global value chains to the country — especially unlike Vietnam, India has a large and growing domestic market.

It has also helped Indian companies — such as Tata, which is now a key part of Apple Inc's global supply chain, and Dixon — to become promising global electronics manufacturing services players. The question is: Can India replicate the same magic for all other PLIs?

tbo.com | TBO Tek Limited
Registered Office: E-78, South Extension Part I, New Delhi - 110049, India
Corporate Office: Plot No. 728, Udyog Vihar Phase I, Gurgaon - 122016, Haryana, India
Tel No.: +91-124-4995999 | Email: corporate@tbo.com
Website: www.tbo.com CIN: L74990DL2009PLC152533

NOTICE OF THE 19th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING RELATED INFORMATION
Notice is hereby given that the 19th (Nineteenth) Annual General Meeting ("AGM") of TBO Tek Limited (the "Company") will be held on **Friday, August 8, 2025 at 3:00 p.m. (IST)** through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM"), to transact the businesses as set forth in the Notice ("Notice") convening the 19th AGM of the Company. The deemed venue of the meeting shall be the registered office of the Company.

In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), read with General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, and subsequent circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") in this regard, including the latest Circular No. 19/2024 dated September 18, 2024, and Circular No. SEBI/HO/CFD-PD-2/P/2024/133 dated October 03, 2024, along with other applicable circulars issued by SEBI in this regard (collectively referred to as the "Circulars"), the Notice, along with Annual Report for the FY 2024-25, has been sent through electronic mode to all the Members whose email addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent ("RTA"/Depository Participant(s)) ("DP") on Friday, July 04, 2025. The dispatch of the Notice and Annual Report to the Members through emails has been completed on July 14, 2025. Pursuant to Regulation 36(1)(b) of the SEBI Listing Regulations, the Company is also sending a letter through the web-link, including the exact path, for accessing the Notice and Annual Report to the Members who have not registered their email addresses. The Company shall also send a physical copy of the Annual Report to those Members who request for the same.

The Notice and Annual Report are also available on the website of the Company at www.tbo.com, website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com and on the website of the stock exchanges where the equity shares of the Company are listed i.e. BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.

Instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM

- In accordance with the provisions of Section 108 and other applicable provisions of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company is pleased to provide to its members, the facility to exercise their right to vote on the businesses set forth in the Notice by electronic means, through both remote e-voting and e-voting at the AGM. The Company shall also provide NSDL as the agency to provide electronic voting facility and participation in the AGM through VC/OAVM.
- The cut-off date for determining the eligibility of Members for voting through remote e-voting and e-voting during the AGM is Friday, August 01, 2025 ("Cut-Off Date"). Only a person whose name is recorded in the Register of Members/Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-Off Date shall only be entitled to exercise voting rights on the resolutions set out in the Notice.
- The remote e-voting period will commence on Tuesday, August 5, 2025, at 9:00 A.M. (IST) and end on Thursday, August 7, 2025, at 5:00 P.M. (IST) and thereafter, the remote e-voting module shall be disabled for voting by NSDL.
- Members who have acquired shares after the dispatch of the Annual Report for the financial year 2024-25 but before the Cut-Off Date are requested to obtain the User ID and password by sending a request to NSDL at evoting@nsdl.com or the Company at corporate@tbo.com by mentioning his/her DP ID and Client ID Folio No. However, if a Member is already registered with the NSDL for remote e-voting, then the Member may use his/her existing User ID and password and cast vote.
- Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting during the AGM. Members who have voted through remote e-voting shall be eligible to attend the AGM, however, they shall not be eligible to vote at the meeting.
- The instructions for remote e-voting, e-voting during the AGM and attending the AGM through VC/OAVM have been provided in the Notice.
- The Company has appointed M/s. Shrin Bhatt (FCS: 8273, COP No.: 9150), on behalf of M/s. Shrin Bhatt & Associates, Practising Company Secretaries, to act as Scrutinizer for conducting the voting process in a fair and transparent manner.
- In case of any query regarding e-voting, please refer Frequently Asked Questions ("FAQs") available on the website of the Company at www.tbo.com and download section at www.evoting.nsdl.com or contact M/s. Pallavi Mahapatra, Senior Manager, NSDL at Plot No. 31, Naman Chambers, Plot C-32, G-Block, 3rd Floor, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400051 at Telephone No. 022-48867000 or send a request at evoting@nsdl.com or write an email to Company Secretary at corporate@tbo.com.
- Members who are holding shares in dematerialized mode and have not registered/updated their email IDs/KYC details are requested to register/update the same with their respective DPs. Members who are holding shares in physical mode and have not registered/updated their email IDs/other KYC details are requested to submit request to update their email IDs, along with supporting documents to the Company's RTA, i.e. KFin Technologies Limited, either at its office or KFin Technologies Limited (Unit: TBO Tek Limited), Selenium Building, Tower B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad-500032, Telangana or by email at atn@nsdl.com.
- On or before 1st April, 2024, as per the SEBI Master Circular dated May 7, 2024, read with SEBI Circular dated June 10, 2024, members holding shares in physical form and who have not completed any of their KYC details viz., PAN, contact details, bank account details and specimen signature, will be eligible (i) to lodge grievance or avail any service request from the RTA, (ii) to receive dividend, only upon completion of KYC details.

For TBO Tek Limited
Sd/-
Neera Chandan
Place: Gurugram
Date: July 14, 2025
Company Secretary and Compliance Officer

Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)
Head Office: 21-Rajendra Place, New Delhi-110008
Corporate Office: NBCC Office Complex, Block 3, East Kirti Nagar, New Delhi - 110023
<https://punjabandsindbank.co.in/>

NOTICE OF THE 15th ANNUAL GENERAL MEETING OF THE BANK TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 15th Annual General Meeting of the Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) on **Tuesday, the 8th of August, 2025 at 11.00 a.m. (IST)** to transact the business as contained in the notice of the AGM.

In compliance of the aforesaid Circulars, electronic copies of the Annual Report 2024-25 containing therein the notice of the 15th Annual General Meeting of the Bank has only been sent to those shareholders whose email addresses are registered with the Bank / Depository Participant(s) and also to those shareholders who have got their email addresses registered with our RTA, MUFG Infinit India Private Limited, pursuant to our newspaper publication published on 8th July, 2025. A copy of the same is available on the website of the Bank i.e. <https://punjabandsindbank.co.in/> and the website of the stock exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com. The Head Office of the Bank is the deemed venue of the Annual General Meeting.

Shareholders holding shares either in physical or demat form, as on the cut-off date may cast their votes electronically on the business as set forth in the Notice of the 15th AGM through the electronic voting system of Central Depository Services Limited (CDSL) ("remote e-voting").

- The business as set forth in the Notice of the 15th AGM will be transacted through remote e-voting and e-voting system at the 15th AGM;
- The Electronic dispatch of the Annual Report 2024-25 containing the notice of the 15th Annual General Meeting of the Bank was completed on **Monday, 14th July 2025**.
- The Register of the Shareholders and Share Transfer Register of the Bank will remain closed on **Wednesday, 30th July 2025 to Tuesday, 5th August 2025** (both days inclusive) for the purpose of updating the 15th Annual General Meeting.
- The record date for reckoning the Shareholders' Right for dividend, e-voting and to participate in AGM through VC / OAVM is **Tuesday, 29th July 2025**. The dividend will be paid to the shareholders within 30 days from the date of declaration of the dividend at the Annual General Meeting. We wish to inform you that as per Section 134 of the Income Tax Act, 1961 (the Act), Bank will be deducting tax, if the dividend amount paid to a shareholder exceeds Rs. 5000 (Rupees Five thousand) and above in a financial year.
- The remote e-voting shall commence at **10:00 a.m. on Friday, 1st August 2025 and end at 5:00 p.m. on Monday, 4th August 2025 and will be disabled thereafter**;
- Any person, who acquires shares of the Bank and becomes a member post-dispatch of the Notice of the 15th AGM and holds shares as on the cut-off date i.e. **Tuesday, 29th July 2025** may follow the procedure as provided in the notice of the AGM to obtain the login ID and password for remote e-voting and e-voting during AGM.
- Shareholders may note that:
- The facility for voting will also be made available during the 15th AGM and those shareholders present at the 15th AGM through VC facility who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not doing so shall be eligible to vote through the e-voting system at the 15th AGM;
- The Shareholders members who have cast their votes by remote e-voting prior to the 15th AGM may also attend the 15th AGM but shall not be entitled to cast their votes again in the meeting.
- Only persons whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting-voting at the meeting.

The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the 15th AGM.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1-800-225-5533.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dahi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futrex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Road, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on toll free no. 1-800-225-5533.

Shareholders are requested to refer the detailed notice of the AGM as available aforesaid for any other information/procedure.

The aggregate results of remote e-voting and e-voting at AGM shall be made available within 2 (two) working days of the AGM at the Bank's website <https://punjabandsindbank.co.in/>, website of the stock exchanges www.nseindia.com and www.bseindia.com and also on the website of CDSL at www.evotingindia.com and

the Annual Report 2024-25 containing the notice of the 15th Annual General Meeting is available at <https://punjabandsindbank.co.in/content/archive-annual>

By order of the Board of Directors
For PUNJAB & SIND BANK
(Saket Mehrotra)
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 14 July, 2025